

भारत सरकार  
विदेश मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2046  
दिनांक 06.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत की विदेश नीति

2046. श्री जुगल किशोर:  
श्री गणेश सिंह:  
श्री आलोक शर्मा:  
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:  
श्री भर्तृहरि महताब:  
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:  
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:  
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत की विदेश नीति बढ़ते वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक गठबंधनों के निर्माण के संदर्भ में किस प्रकार विकसित हुई है; और

(ख) सरकार ने अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने और रणनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जी-20 और आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों से किस प्रकार लाभ उठाया है?

उत्तर  
विदेश राज्य मंत्री  
[ श्री कीर्ति वर्धन सिंह ]

(क) भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित होती रहती है, जिसमें विश्व भर में रह रहे और काम करने वाले भारतीयों के हित भी शामिल हैं। यह देश

की बढ़ती प्रतिष्ठा और विश्व मंच पर अधिक जिम्मेदारियां संभालने की क्षमताओं से भी परिलक्षित होता है। भारत की विदेश नीति का प्रमुख केंद्र इसका निकटस्थ और विस्तृत पड़ोसी क्षेत्र है। इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध 'प्रथम पड़ोस नीति', 'एक्ट ईस्ट नीति', 'थिंक वेस्ट नीति' और 'कनैक्ट सेंट्रल एशिया नीति' तथा 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (सागर) पहल द्वारा निर्देशित हैं। इन नीतियों का उद्देश्य संबंधित देशों के साथ हमारे सहयोग को व्यापक रूप से बेहतर बनाना है। ब्रिक्स, एससीओ और क्वाड जैसी विभिन्न बहुपक्षीय पहलों में भारत की सदस्यता तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधक अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई), वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन और भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना में भारत के अपने नेतृत्व से देश के बढ़ते हित और सहभागिताएं भी परिलक्षित होती हैं।

(ख) आसियान के साथ भारत का संबंध हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है और हमारी एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला है। आसियान-भारत संबंधों को 2012 में रणनीतिक साझेदारी स्तर तक और 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाया जाना एक स्वाभाविक प्रगति थी, जो यह दर्शाता है कि आसियान के साथ हमारे संबंध 1992 में क्षेत्रीय वार्ता साझेदार (सचिव स्तर), 1996 में वार्ता साझेदारी (मंत्री स्तर) और 2002 में शिखर सम्मेलन स्तरीय साझेदारी (नेताओं के स्तर) से आगे बढ़ गए हैं।

आसियान + 1 (भारत) संरचना में भागीदारी के अलावा, आसियान क्षेत्र के साथ भारत की भागीदारी से संबंधित अन्य मंचों में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएस), आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ), आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) और विस्तारित आसियान समुद्री मंच (ईएएमएफ) शामिल हैं।

1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत की जी-20 अध्यक्षता से यह अवसर प्राप्त हुआ कि जी-20 में अपनी विकास पहलों पर प्रकाश डाला जाए और ग्लोबल साउथ के देशों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में सर्वसम्मति से अंगीकृत जी-20 नेताओं के घोषणापत्र में भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की विभिन्न विकासात्मक प्राथमिकताओं के संबंध में महत्वाकांक्षी और कार्रवाई-उन्मुख परिणामों को दर्शाया गया, जिसमें एसडीजी संबंधी प्रगति में तेजी लाना, हरित

विकास और पर्यावरण हेतु जीवनशैली (लाइफ) पहल, त्वरित और समावेशी विकास को बढ़ावा देना, 21 वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, डिजिटल सार्वजनिक संरचना की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा महिलाओं के नेतृत्व में विकास शामिल हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और भारत-मध्य-पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे का आरंभ, उन साझेदारियों की श्रृंखला को प्रतिबिंबित करता है, जिन्हें भारत जी-20 में अपने कार्यकलापों के भाग के रूप में स्थापित करने में सक्षम रहा है।

\*\*\*\*\*